कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ–3/50/2014/10–11/15/3284 भोपाल, दिनांक 30-9-20

प्रति,

श्री बिजेन्द्र स्वरूप,
सहायक वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः– अशोकनगर एवं शिवपुरी जिले में लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना (केन–बेतवा लिंक परियोजना) के निर्माण हेतु 968.24 हेक्टेयर वन भूमि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-08/2016-FC दिनांक 12.02.2019

––0––

महोदय,

विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी की गयी सैद्वांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर निम्नानुसार प्रेषित हैः–

S.N.	Conditions	Compliance
1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है।
2	The compensatory afforestation shall be done over equal non-forest land (NFL) to the forest area proposed to be diverted within a period of three years with effect from the date of issue of stage II clearance and maintained thereafter in accordance with the approved plan in consultation with the state forest department at the cost of the user agency. At least 1000 saplings per hectare shall be planted over 968.24 hectare (968240). if this is not possible to plant these many seedlings in the identified NFL the balance seedling will be planted in degraded forest land as per the prescription of the working plan at the cost of the user agency. In such case CA cost will be revised and duly approved by competent authority and deposited online in the CAF managed by CAMPA.	क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये आवेदक संस्था द्वारा 1042.77 हेक्टेयर गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है। इस गैर वनभूमि का नामांतरण वन विभाग के नाम हो चुका है। आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई इस गैर वनभूमि का DSS analysis करने पर 490 हेक्टेयर भूमि घने वन में आ रही है। अतः क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि में 4,45,424 पौधे रोपित किये जायेगे। शेष पौधें बिगड़े वनों में रोपित किये जायेगे। इस हेतु 600 हेक्टेयर बिगड़े वनों का चयन किया गया है तथा इस बिगड़े वनों में 5,50,000 पौधें रोपित किये जायेगे। इस प्रकार इस प्रस्ताव में गैर वनभूमि पर 4,45,424 तथा बिगड़े वनों में 5,50,000 इस प्रकार कुल 9,95,424 पौधें रोपित किये जायेगे। सभी स्थलों की क्षतिपूर्ति रोपण योजना तैयार कर ली गई है तथा इसकी एक–एक प्रति संलग्न है।

–2–

3	The user agency shall submit the revised cost benefit analysis after considering the ecological cost of being diverted forest area.	आवेदक संस्था द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है जो परिशिष्ट–I पर संलग्न है।
4	The state government and the user agency shall ensure that the water flow downstream shall be regulated in line with the natural flow regime and in the lean period 100% of the existing flow regime should be maintained while in the non-lean period the prescribed minimum flow of the water by hydrology and aquatic biodiversity experts should be ensured. The minimum flow of water in the ken river will be maintained till it joins the Yamuna to save wildlife including crocodiles and othe aquatic animals. The user agency shall also construct a number of concrete dykes across smaller streams going off from the main reservoir which during FRL shall be over flown but which during lean season shall dam up small isolated water bodies for the benefit of the wildlife.	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट– II पर संलग्न है।
5	The state government and the user agency shall ensure that the canal should be realigned to minimize the use of forest land for construction of canal.	इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा अवगंत कराया गया है कि उनके द्वारा नहर के सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद वर्तमान alignment को सबसे उपयुक्त पाया है।
6	Along the canal alignment, structural interventions shall be carried out at wildlife cross over points which are duly camouflaged and mimic nature at cost to the user agency so that dispersal is not hindered.	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट– III पर संलग्न है।
7	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a survey of India toposheet of 1:50000 scale.	आवेदक संस्था द्वारा 1:50000 scale की toposheet पर इसे अंकित कर दिया गया है, जो परिशिष्ट– IV पर संलग्न है।
8	The identified non-forest land to be transferred and mutated in favour of the state forest department for raising compensatory Afforestation shall be notified as reserved forest under section-4 or protected forest under section-29 of the Indian forest act, 1927 or under the relevant section(s) of the local forest act. The nodal officer must report compliance within a period of 6 month from the date of grant of final approval and send a copy of the notification declaring the non-forest land under section 4 or section 29 of the Indian forest act 1927 or under the relevant section of the local forest act as the case may be to this ministry for information and record.	क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई 1042.77 हेक्टेयर गैर वनभूमि का नामांतरण वन विभाग के नाम हो चुका है, जो परिशिष्ट– V पर संलग्न है।

9	The user agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of Ad-hoc CAMPA of the concerned state through online portal. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये आवश्यक राशि रू. 45,55,07,389 का भुगतान ई–पोर्टल के माध्यम से किया है। इस राशि में मदा एवं जल संरक्षण कार्यों की राशि भी सम्मिलित है।
10	The user agency shall provide additionally 25% of the CA cost towards soil and moisture conservation measures in the proposed CA area as per site requirement and the said amount may be deposited in the account of Ad-hoc CAMPA of the concerned state through online e-portal only.	मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों की राशि वृक्षारोपण योजना में सम्मिलित है।
11	The user agency shall transfer online the net present value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal as per the orders of the hon'ble Supreme court in India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in writ petition (civil) no 202/1995 and the guidelines issued requisite funds shall be transferred through online portal into Ad-hoc CAMPA account of the state concerned;	आवेदक संस्था द्वारा नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि रू. 67,67,80,960 का भुगतान ई–पोर्टल के माध्यम से किया है।
12	Any fund received from the user agency under the project and deposited in the state forest department account except the funds realize for regeneration/demarcation of safety zone shall be transferred through online portal into Ad-hoc CAMPA account of the state concerned;	सभी भुगतान ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद में किये गये हैं।
13	The user agency should ensure that the compensatory levies (CA cost ,NPV etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank online only Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the stage-I clearance;	सभी भुगतान ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद में किये गये हैं।
14	At the time of payment on the net present value (NPV) at the then prevailing rate the user agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV if so determined as per final decision of the hon'ble supreme court of India;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट– VI पर संलग्न है।

15	The approved catchment area treatment (CAT) plan shall be implemented at the cost of user agency the commensurate cost of CAT plan will be deposited in compensatory Afforestation fund of state;	आवेदक संस्था द्वारा catchment area treatment (CAT) plan प्रस्तुत किया गया है, जो परिशिष्ट– VII पर संलग्न है। इस (CAT) plan की तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी द्वारा पत्र दिनांक 20.05.2015 से जारी की गई है। इस स्वीकृति के अनुसार वन क्षेत्र में रू. 1079.92 लाख के कार्य तथा राजस्व क्षेत्र में रू. 3659.11 लाख के कार्य किये जायेगे। प्रस्ताव में वन क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों के लिये रू. 1079.92 लाख की राशि आवेदक संस्था से ई–पोर्टल के माध्यम से भुगतान करवाई गई है।
16	The state government shall submit a certificate that site for CA is suitable and free from all encroachment and the other circumstances under the signature not below the rank of nodal officer (FCA) in the state government;	क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी भूमियां वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। इस संबंध में वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रत्येक प्रोजेक्ट के अंत में प्रमाण पत्र अंकित किया है। आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि में से कुछ स्थलों का निरीक्षण नोडल अधिकारी द्वारा भी किया गया है। निरीक्षण में सभी स्थल रोपण हेतु उपयुक्त पाये गये हैं।
17	User agency shall obtain the environment clearance as per the provisions of the environment of the environment (protection) act ,1986 if required;	आवेदक संस्था द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है, जो परिशिष्ट– VIII पर संलग्न है।
18	The state government shall ensure that the forest land located between FRL and the FRL-4 meters may be afforested by planting appropriate indigenous tree species;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट– IX पर संलग्न है।
19	The user agency shall undertake afforestation along the periphery of the reservoir;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट– X पर संलग्न है।
20	User agency shall provide free water for the forestry related projects;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट– XI पर संलग्न है।
21	Layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the central government;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट– XII पर संलग्न है।

22	No labour camp huts shall be established on the forest land;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट– XIII पर संलग्न है।
23	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal and the under no circumstances be transferred to any other agency department or person;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट– XIV पर संलग्न है।
24	Felling of tree if unavoidable on the forest land being diverted shall be reduced to the bare minimum and trees should be felled under strict supervision of the state forest department. Moreover it shall be ensure that wherever possible maximum marked trees for felling should be translocated in the consultation of the state forest department;	वन विभाग द्वारा न्यूनतम वृक्षों का पातन किया जायेगा। इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट– XV पर संलग्न है।
25	The state government ensure that the user agency shall implement the R&R plan as per the R&R policy of the state government in consonance with national R&R policy government of India before the commencement of the project work. The said R&R plan will be monitored by the state government /Regional office of MoEF & CC along with indicators for monitoring and expected observable milestone;	आवेदक संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य शासन के पत्र क्रमांक/878 दिनांक 16.05.2018 से इस प्रस्ताव में प्रभावित परिवारों के लिये विशेष पुर्नवास पैकेज की स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत पैकेज के अनुसार ही विस्थापन का कार्य किया जा रहा है तथा यह कार्य पूर्णतः की ओर है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट– XVI पर संलग्न है।
26	To prevent illegal occupation/ encroachment of the forest land by the families to be displaced from the project site the user agency shall ensure that each family being displaced from the project site actually acquires and settles on non-forest land. Apart from taking other measures to achieve the said objective as a measure to discourage the project affected families from encroachment on the forest land, payment of annuity for a period of atleast five years at the rate of the minimum wages payable to the unskilled person for 200 person days per annum to each adult member of the project affected families on receipt of a certificate signed by a forest officer not below the rank of a Range officer having jurisdiction over the area where such person has settled after displacement from the project site should be incorporated in the R&R plan payment of the said annuity should be an additionally and not in replacement of any of the benefit to be accrued to the project affected persons as per the approved R&R plan;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट– XVII पर संलग्न है।

27	The user agency shall track location of each displaced family and ensure none of them encroach/occupy forest land in support of compliance to the said condition at least for five years from the date of taking of possession of the forest land the user agency shall submit an annual certificate to the PCCF Madhya Pradesh that none of the persons displayed from the project land has encroached/settled in the forest land during the year;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट– XVIII पर संलग्न है।
28	The forest department shall prepare a plan of action to utilize the water potential available nearby for the benefit of forest crop and also to the wild animal at the cost of the user agency;	वन विभाग द्वारा आवश्यक पानी मांगने पर आवेदक संस्था सहमत है।
29	A plan for conservation of wildlife will be made by the user agency in consultation with the PCF (wildlife) to be implemented at the cost of user agency;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट– XIX पर संलग्न है।
30	User agency in consultation with the state forest department shall create and maintain alternate habitat /home for the avifauna whose nesting tress are to be cleared in this project. Bird nests artificially made out of ecofriendly materials shall be used in the area, including forest area and human settlement adjoining the forest area being diverted for the project;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट– XX पर संलग्न है।
31	State government shall complete settlement of rights in terms of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers(Recognition of forest right) Act 2006 if any on the forest land to be diverted submit the documentary evidence as prescribed by this ministry in its letter no 11.9/1998-FC(pt.) dated 03.08.2009 read with 05.07.2013 in support thereof;	आवेदक संस्था द्वारा इस संबंध में प्रमाण पत्र पूर्व में ही प्रस्तुत किया जा चुका है।
32	The user agency shall provide alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest area;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट– XXII पर संलग्न है।
33	Boundary of the forest land proposed to be diverted shall be demarcated on ground at the project cost by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars each inscribed with its serial number forward and back bearing distance from pillar to pillar and GPS co-ordinates;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट– XXIII पर संलग्न है।

34	The state government shall maintain the character of the project as an irrigation project and to ensure continued benefit to the farmers in the command area no more diversion water from the project for the industrial projects will be permitted in future;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट– XXIV पर संलग्न है।
35	Any other condition that the concerned Regional offices of this ministry may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests& wildlife with the approval of the competent authority;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट– XXV पर संलग्न है।
36	The user agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above conditions to the state government concerned regional office and this ministry by the end of march of every year regularly;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट– XXVI पर संलग्न है।
37	The user agency and the state government shall ensure compliance to provisions of the all acts, rules, regulations, guideline, relevant hon'ble court orders(s) if any pertaining to this project for the time being in force as applicable to the project;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट– XXVII पर संलग्न है।

आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन तथा क्षतिपूर्ति रोपण योजनाऐं एवं अन्य अभिलेख संलग्न कर अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार, की औपचारिक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

30/9/2022

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/एफ–3/50/2014/10–11/15/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, 1250, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), शिवपुरी वृत्त शिवपुरी,, मध्यप्रदेश।
3. वनमण्डलाधिकारी, (सामान्य) वन मण्डल शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
4. वनमण्डलाधिकारी, (सामान्य) वन मण्डल अशोकनगर, मध्यप्रदेश।
5. कार्यपालन यंत्री, लोअर ओर परियोजना बांध, जल संसाधन संभाग चंदेरी, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

30/9/2022

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

PROFORMA FOR VERICICATION OF DEPOSITS IN COMPENSATORY AFFORESTATION FUND

1	Name of Regional Office	Bhopal
2	State/Distt/Forest Division to which the proposal relates	State : M.P. District : Ashoknagar and Shivpuri Division : Ashoknagar and Shivpuri
3	Name of User Agency, nature of proposal	WRD
4	nature and category of proposal	Irrigation
5	Proposal number	FP/MP/IRRIG/7403/2014
6	Extent of forest area involved	968.24 ha.
7	Whether original or extension	Original
8	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional forest area and if so, specify	NA
9	Date of Ist stage clearance	12-02-2019
10	Extent of CAMPA charges, head wise viz,: (a) Compensatory Afforestation: (b) Additional CA (c) Penal CA (d) Catchment Area Treatment (e) NPV for Wildlife Area (f) Additional Charges for diversion of area falling under notified/protected areas (g) Net Present Value (h) Any Other Charges /levies (Penal Net Present Value)	a) 45,55,07,389 /- b) N/A c) N/A d) 10,79,92,000/- e) N/A f) N/A g) 67,67,80,960 /- h) N/A
	Total	**1,24,02,80,349/-**

11	Whether payment made through challan of othervise in case of online payment details of challan				Through Challan		
12	Details of deposits						
S No.	Type of deposit (NPV/CA/IWMP/Others (specify))	Whether by RTGS/DD/ NEFT (specify)	UTR / DD No.	Amount deposited (Rs.)	Date of deposit	Name of Bank from which amout transferred to account of CAF	Bank Account of CAF managed by CAMPA in which fund deposited
1	CA	RTGS/ NEFT		20,55,07,389 25,00,00,000	13/05/2020 29/02/2020	Corporation Bank , New Delhi -110003	Corporation Bank
2	Catchment Area Treatment Plan			79,92,000 10,00,00,000	21/08/2020 07/01/2020		
4	NPV			17,13,11,160 20,54,69,800 24,00,00,000 6,00,00,000	10/09/2019 20/08/2019 09/08/2019 01/08/2019		
Total				**1,24,02,80,349/-**			

30/9/2020

(Sunil Agarwal)
APCCF (Land Management)
& Nodal officer FCA
Madhya Pradesh, Bhopal